कचरा निष्पादन

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

24 मार्च, 2022

कुछ गाँवों को मिला कचरा निष्पादन का बुनियादी ढाँचा: पैनल

लोकसभा में बुधवार को पेश जल संसाधनों पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल तरल कचरा प्रबंधन के लिए बुनियादी ढाँचा हासिल करने वाले सिर्फ 12 फीसदी गाँवों ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढाँचे का कार्यान्वयन भी पीछे रह गया, जिसमें केवल 22% लक्षित गाँवों को 2021-22 के दौरान 7 फरवरी तक कवर किया गया था।

अपने पहले चरण में, स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य हर ग्रामीण परिवार में शौचालय उपलब्ध कराना था और 2019 में अपने लक्ष्य को हासिल करने का दावा किया। बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए ठोस अपशिष्ट, खाद के गड्ढे और बायोगैस संयंत्र, ग्रेवाटर प्रबंधन, सोख गड्ढ़े, और मल कीचड़ का उपचार आदि लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। महामारी के साथ प्रगति भी धीमी हो रही है।

पैनल ने जल शक्ति मंत्रालय से केन्द्र की प्रमुख योजनाओं में से एक के लिए "निराशाजनक प्रदर्शन" के रूप में वर्णित के बारे में जवाब माँगा लेकिन मंत्रालय की प्रतिक्रिया ने राज्यों पर यह कहते हुए दबाव डाला कि उन्होंने अपने लक्ष्यों का अनुमान लगाया था। "हालाँकि, विभिन्न समीक्षा बैठकों में राज्यों द्वारा खुलासा किया गया है कि एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों को लेने में शामिल जटिलता के कारण और यह कहा की COVID-19 महामारी की पुनरावृत्ति के कारण, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में जमीनी स्तर पर बाधा उत्पन्न हुई है और प्रगति कम रही है।

भाजपा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाले पैनल ने इस तरह की "जटिलताओं" और बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए "उपचारात्मक उपायों" के बारे में सूचित करने के लिए कहा। इसने मंत्रालय से लोगों को अपने गाँवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन सुविधाओं की माँग करने के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने का आग्रह किया।

कम फंड उपयोग

मंत्रालय की अन्य प्रमुख योजना जल जीवन मिशन के संबंध में जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पीने योग्य नल का पानी लाना है। समिति ने कम धन के उपयोग के लिए सरकार को फटकार लगाई जबकि बजट में ₹50,011 करोड़ आवंटित किए गए थे। योजना के लिए संशोधित अनुमानों को घटाकर ₹45,011 कर दिया गया था और अब तक किया गया वास्तविक व्यय केवल ₹28,238 करोड़ है। वास्तव में केवल तीन राज्यों- हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय ने केंद्र से अपने आवंटन का पूरी तरह से उपयोग किया है। पैनल ने नोट किया कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के साथ कुछ सबसे बड़े राज्यों का प्रदर्शन सबसे खराब है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसका लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पीने योग्य नल का पानी पहुँचाना है।
2. यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(क) केवल 1

(ख) केवल 2

(ग) 1 और 2 दोनों

(घ) कोई नहीं

Expected Question (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements regarding Jal Jeevan Mission.

1. It aims to bring potable tap water to all rural homes by 2024.
2. It comes under Jal Shakti ministry.

which of the above statements is/are correct?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) None

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. "समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण के आधार पर जल जीवन मिशन हर घर को पोर्टेबल नल का पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है"। उपरोक्त कथन के आलोक में भारत में पानी के उपयोग और इसके निपटान पैटर्न का आलोचनात्मक परीक्षण करें। (250 शब्द)

Q. "Based on the community centric approach Jal Jeevan Mission ensures to provide portable tap water to every household". In the light of the above statement critically analyse the water usage and its disposal pattern in India. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।